Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अप्रैल (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा पुलिस चलाएगी मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान 3
- हरियाणा का पहला RPTO 3
- दिव्यांगजनों को लेकर हरियाणा सरकार का एमेजॉन कंपनी से हुआ समझौता 4
- खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ 5
- चांग गाँव होगा महाग्राम योजना में शामिल 5
- हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) की शुरुआत की 6
- हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी 6
- आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार 6
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने एसएमडीए, 2023 विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी 7
- हरियाणा सरकार ने पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में किया संशोधन 8
- रेंडमाईजेशन एंड रियल टाइम इंस्पैक्शन साफ्रटवेयर (ड्रग विंग) 8
- हरियाणा ने मिड-डे-मील योजना के बजट में की 72 फीसदी की बढ़ोतरी 9
- 'चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान' 9
- हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा काम 10
- जीएसटी संग्रहण में हरियाणा पहुँचा देश में चौथे नंबर पर 10
- मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी-20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन 11
- 'मिलेट्स एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा' विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम 12
- मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 32 करोड़ की दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया 12
- 5 दिवसीय सांग महोत्सव का शुभारंभ 13
- हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा काम 14
- पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी 14
- 'प्रापर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल' लॉन्च 15
- आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और हिसार एयरपोर्ट के बीच रेल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी 15
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण 16
- स्कूल शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन 16
- ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी विश्वकप स्टेप वन-1 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता 17
- 'हरियाणा किराये पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023' अधिसूचित 18
- प्रदेश में सीसीटीएनएस होगा मेघराज क्लाउड में स्थानांतरित 19
- मुख्यमंत्री ने प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा सहित 3 नई ई-गवर्नेंस पहलों की शुरुआत की 20
- 131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति 21
- हरियाणा में पत्रकारों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए हुई 22
- हरियाणा के बिजली निगमों ने ए+ ग्रेड हासिल कर किया श्रेष्ठ प्रदर्शन 22
- हरियाणा विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन 23

नोट :

हरियाणा

हरियाणा पुलिस चलाएगी मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस समस्त राज्य में मानव तस्करी के खिलाफ अप्रैल माह में एक महीने का अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से पुलिस का उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक चलेगा।
- इस अभियान में सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होंगी। इस दौरान हरियाणा पुलिस बचाव अभियान चलाते हुए मानव तस्करी के पीड़ितों को पुनर्वास प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी।
- हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उसके आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- फील्ड यूनिट्स को भेजे गए संदेश में सभी एसपी और डीसीपी को अभियान चलाने के लिये कहा गया है। सीपी और आईजी/एडीजी रेंज साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। लापता बच्चों और वयस्कों की संख्या का पता लगाने और भिखारियों और मज़दूरों को बचाए जाने पर महीने के अंत में फील्ड इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
- इस दिशा में, पुलिस गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों की फिर से जाँच करेगी और आस-पास के राज्यों में आश्रयों और बाल गृहों में पुलिस टीमों को यह देखने के लिये भेजेगी कि उनमें से कोई वहाँ रह रहा है या नहीं। गुमशुदा बच्चों के मामले धारा 363-366 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं, जबकि लापता वयस्कों के मामले 346 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2022 में 3379 लापता महिला और 6340 पुरुष वयस्कों का पता लगाया। साथ ही, लापता 1144 लड़कों और 1426 लड़कियों को भी बरामद किया। इसके अतिरिक्त, इसने 41 बंधुआ मजदूरों को भी मुक्त कराया।
- इसी अवधि में, राज्य अपराध शाखा की 22 एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) ने लापता 316 पुरुष वयस्कों और 373 महिलाओं का पता लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लापता व्यक्ति का मामला आगे की जाँच के लिये राज्य अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया जाता है, अगर यह ज़िले में चार महीने से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है।
- अभियान के माध्यम से हरियाणा पुलिस का लक्ष्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अन्य राज्य पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बिछुड़ों को उनके प्रियजनों के साथ फिर से जोड़ते हुए परिवार में मुस्कान वापस लाना है।

हरियाणा का पहला RPTO

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के उपनिदेशक (बागवानी) एवं ड्रोन प्रशिक्षक डॉ. सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने करनाल ज़िले के फूसगढ़ गाँव स्थित सामुदायिक केंद्र भवन में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (आरपीटीओ) स्थापित कर दिया है। यह हरियाणा का पहला सरकारी आरपीटीओ है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि ड्रोन का उपयोग देश व प्रदेश की सुरक्षा से लेकर अब खेत खलिहानों तक होने लगा है। पिछले दो तीन सालों से कृषि में ड्रोन के उपयोग को राज्य सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। यही कारण है कि विभिन्न कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है।
- हाल ही में करनाल की महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान अटारी क्षेत्र में सर्वाधिक 700 एकड़ में नैनो यूरिया, डीएपी, रसायनों का छिड़काव सभी फसलों पर करने में प्रथम पुरस्कार मिला है।
- हरियाणा सरकार ने एक संस्था दृष्या यानि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का गठन किया है। यही संस्था करनाल में स्थापित आरपीटीओ का संचालन करेगी।
- एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च-2024 तक आरपीटीओ करनाल का करीब 500 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ड्रोन पायलेट बनाने का लक्ष्य है। अभी आरपीटीओ के पास दो ड्रोन उपलब्ध हो गए हैं।
- आरपीटीओ को संचालित करने वाली दृष्या के चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जबकि भारतीय नौ सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, विंग कमांडर गिरिराज पूनिया को इसका सीईओ बनाया गया है। आईएएस टीएल सत्यप्रकाश को इसका प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
- ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण लेने के लिये युवाओं को मैट्रिक पास होना आवश्यक है। इसके लिये उसके पास आधार कार्ड, पास पोर्ट हो। साथ ही, उसकी उम्र 18 से 65 साल के मध्य होनी चाहिये। इच्छुक युवाओं को आरपीटीओ में पंजीकरण कराना होगा।
- कृषि क्षेत्र में खाद से लेकर कीटनाशक छिड़काव में लगातार ड्रोन की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र, खनन क्षेत्र, नेशनल हाईवे और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित ड्रोन पायलट की मांग भी बढ़ती जा रही है।
- उपनिदेशक (बागवानी) एवं ड्रोन प्रशिक्षक डॉ. सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभी पाँच दिन के विशेष प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाकर सरकार को भेजी गई है।
- इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) की ओर से निर्धारित फीस 65 हज़ार (जीएसटी अतिरिक्त) है, लेकिन इससे कम करके 25 हज़ार रुपए की फीस का प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा गया है। सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद उसी हिसाब से फीस तय व प्रशिक्षण दिवस निर्धारित कर दिये जाएंगे।

दिव्यांगजनों को लेकर हरियाणा सरकार का एमेजॉन कंपनी से हुआ समझौता

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि राज्य सरकार का एमेजॉन के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत प्रदेश के 10 हज़ार युवाओं को एमेजॉन कंपनी में रोज़गार दिया जाएगा। इनमें 1500 दिव्यांगों को भी नौकरी देनी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांगों के लिये लघु सचिवालय में भूतल पर स्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में 3 अप्रैल से हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये सभी दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
- राज्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों की फीस को नि:शुल्क कर दिया गया है।
- प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बैकलॉग भरा जाएगा, जिसके लिये चार सदस्यीय का कमेटी का गठन किया जा चुका है। एडेड कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं, उनमें कट लगाया जाएगा और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा। इसके साथ-साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- विदित है कि एडेड कॉलेजों में अब तक अनुसूचित जाति वर्ग व दिव्यांगजनों को उनके रोस्टर अनुसार पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। दिव्यांग की सीट पर सामान्य लोग नौकरी में लग गए हैं।

नोट :

खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 अप्रैल, 2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की कार्यकारी निदेशक ललिता शर्मा ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत ज़िले में साई के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, बहालगढ़ में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता में देशभर की 96 महिला तीरंदाजों ने भाग लिया है तथा विजेताओं को पाँच लाख रुपए तक के इनाम दिये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि 3 और 4 अप्रैल को हो रही प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय तीरंदाजी संघ और हरियाणा तीरंदाजी संघ मिलकर कर रहे हैं।
- प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को साढ़े 37 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।
- प्रतियोगिता में रिकर्व सीनियर में स्वर्ण पदक जीतने पर पाँच लाख, रजत पदक पर तीन लाख व काँस्य पदक पर दो लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जूनियर में स्वर्ण पदक विजेता को तीन लाख, रजत पदक विजेता को दो लाख व काँस्य पदक विजेता को एक लाख रुपए तथा कैडेट में स्वर्ण पदक पर एक लाख, रजत पर 80 हज़ार व काँस्य पर 50 हज़ार रुपए मिलेंगे।
- इसके अलावा कंपाउंड श्रेणी के सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता को ढाई लाख, रजत पदक जीतने पर डेढ़ लाख व काँस्य पदक जीतने पर एक लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जूनियर में स्वर्ण पदक विजेता को डेढ़ लाख, रजत पदक विजेता को एक लाख व काँस्य पदक विजेता को 50 हज़ार तथा कैडेट में स्वर्ण जीतने पर 50 हज़ार, रजत पदक पर 40 हज़ार व काँस्य पर 25 हज़ार रुपए मिलेंगे।

चांग गाँव होगा महाग्राम योजना में शामिल

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के भिवानी ज़िले के गाँव चांग में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बताया कि चांग गाँव को 'महाग्राम योजना'में शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'महाग्राम योजना'के तहत प्रदेश के उन सभी गाँवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिस गाँव की आबादी दस हज़ार से अधिक है। जिन गाँवों की आबादी दस हज़ार से कम तथा आठ हज़ार से ज्यादा है, उन गाँवों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) लगाए जाएंगे।
- इस योजना के तहत ही चांग गाँव में सीवरेज सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि लार्ड स्वराज पॉल संस्था के साथ मिलकर चांग गाँव के स्कूल के भवन का नवीनीकरण कराया जाएगा।

नोट :

हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में 'स्टार्टअप संगोष्ठी और उद्योग प्रज्वलित, 2023' का उद्घाटन कर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों के लिये संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी आदि के लिये ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) राज्य में युवाओं को पायलट ड्रोन प्रशिक्षण देगी, जिससे युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स वेयरहाउस, इनोवेशन कैंपस और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को भी प्रोत्साहन देने का काम किया है।
- राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में स्थायी खनन अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिये भी ड्रोन का उपयोग कर रही है।
- सरकार राज्य में पराली जलाने पर निगरानी और रोकथाम के लिये ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से पराली जलाने के मामले पिछले साल की तुलना में 47 फीसदी कम हो गए हैं।

हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।
- विदित है कि वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिये इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री निर्धारित योग्यता थी।
- वित्त एवं योजना अधिकारी, प्रधानाचार्य (फुटवियर), प्रशिक्षण अधिकारी (बीटीसी) शिक्षुता तथा प्लेसमेंट अधिकारी के नये सृजित पदों को भरने हेतु नियमों में प्रावधान किया गया है तथा जो पद समाप्त हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं, उन पदों को नियमों से हटाया गया है।
- कंप्यूटर पर कार्य करने की प्रवीणता लाने के लिये कंप्यूटर एप्रीशिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) पास करने का प्रावधान किया गया है।

आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदा को मंजूर किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुँच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है।
- चूँकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया गया है।
- इस नीति के अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष निजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
- हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य सरकार के तहत आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में पेसेंट के रूप में दाखिल होकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं।
- कुछ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की पुरानी बीमारी के रोगियों के बाह्य उपचार के दौरान भी प्रतिपूर्ति की जाएगी क्योंकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों में बाह्य रोगियों को उपचार कराने के लिये कोई दवा निर्धारित नहीं है।
- निश्चित पैकेज दरों को आयुष की सभी धाराओं अर्थात आयुर्वेद (96 पैकेज), योग (27 पैकेज) और प्राकृतिक चिकित्सा (30 पैकेज), यूनानी (85 पैकेज), और सिद्ध (49 पैकेज) में परिभाषित किया गया है।
- इस नीति के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल कर्मचारियों से निश्चित पैकेज दरों पर शुल्क लेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में संबंधित विभाग को बिल जमा करने के बाद की जाएगी। कमरे का किराया भी कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार तय किया जाएगा, जो संबंधित अस्पताल द्वारा पात्रता के अनुसार लिया जाएगा और पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होगा।
- राज्य के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के माध्यम से इनडोर दाखिल होने के दौरान गैर-पैकेज उपचार के मामले में भी कमरे के किराए की पात्रता, प्रयोगशाला दरों और प्रवेश के दौरान दी गई दवाओं की लागत के बराबर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इस नीति के तहत दवाओं की प्रतिपूर्ति योग्य सूची भी तैयार की जाएगी, जो निजी आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में इनडोर प्रवेश के दौरान पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने एसएमडीए, 2023 विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA), 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- यह मसौदा-विधेयक सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर, स्थायी और संतुलित विकास के लिये जीवन की गुणवत्ता और रोज़गार के अवसरों के सृजन के माध्यम से निवासियों को प्रदान किये जाने वाले उचित जीवन स्तर और एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढाँचे के लिये एक दृष्टि विकसित करने का उद्देश्य रखता है।
- इसके अलावा, इस विधेयक के बनने से शहरी सुविधाओं का विकास और प्रावधान, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत् प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास भी होगा।
- सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA)] गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), फरीदाबाद और पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA)] पंचकुला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA)] सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर और संतुलित विकास के लिये एक दृष्टि विकसित करना है। प्राधिकरण द्वारा शहरी सुविधा और ढाँचागत विकास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

नोट :

- सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, परिवहन मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम सोनीपत के महापौर एवं वरिष्ठ उप महापौर तथा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अथॉरिटी के पदेन सदस्य होंगे।

हरियाणा सरकार ने पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में किया संशोधन

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप-नियम (2क) में संशोधन का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएँ तथा चारे को उगाने के लिये अब शामिलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिये पट्टे पर ले सकेंगी।
- इसके लिये गौशालाओं में पट्टा-धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पटो अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा।
- इन नियमों को 'पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023' कहा जाएगा।
- उक्त संशोधन के बाद, अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिये कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी।
- धार्मिक संगठन को समाज के लिये परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है जिसे ज़िला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।
- शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरांत प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।
- शामलात देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिये 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।
- गौशाला निर्माण के बाद गौचरण के लिये चिन्हित भूमि में से 1.5 एकड़ भूमि प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये चारे की खेती हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।

रेंडमाईजेशन एंड रियल टाइम इंस्पैक्शन साफ्रटवेयर (ड्रग विंग)

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किये गए ड्रग लाईसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण को करने हेतू रेंडमाईजेशन एंड रियल टाइम इस्पैक्शन सॉफ्टवेयर (ड्रग विंग) की शुरूआत की है।

प्रमुख बिंदु

- इस सॉफ्टवेयर को लांच करने वाला हरियाणा देशभर में पहला राज्य है। इस सॉफ्टवेयर को पायलट आधार पर पंचकूला ज़िला में लागू किया जाएगा तथा इसके उपरांत राज्य के अन्य ज़िलों में लागू किया जाएगा।
- इस सॉफ्टवेयर की शुरूआत प्रथम चरण में ड्रग विंग के लिये की गई है तथा द्वितीय चरण में फुड विंग को शामिल किया जाएगा। निरीक्षण के लिये अधिकारी के मोबाइल ऐप पर रेंडम लाईसेंसधारी यूनिट के नाम जाएंगे।

नोट :

- इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रग कंट्रोल अधिकारी को रेंडम तरीके से ड्रग यूनिट के निरीक्षण हेतु डयूटी दी जाएगी तथा महीने के अनुसार इन अधिकारियों को निरीक्षण का लक्ष्य भी दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा। ऐसी सभी ड्रग यूनिट का निरीक्षण ऑनलाइन और रियल टाइम होगा।
- इसमें अधिकारियों को जीयो टेगिंग और लोकेशन भी साझा करनी होगी तथा तुंरत उसी समय अपनी निरीक्षण रिपोर्ट लाईसेंसिंग प्राधिकरण और उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन सोंपनी होगी। निरीक्षण के लिये संबंधित अधिकारियों को कंट्रोलिंग अधिकारियों से मंजूरी भी लेनी होगी।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में 32581 खुदरा एवं थोक ड्रग लाईसेंसधारक हैं।

हरियाणा ने मिड-डे-मील योजना के बजट में की 72 फीसदी की बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हुई मिड-डे-मील योजना के लिये राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएमपीओएसएचएएन) के तहत 14,409 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिये बजट में लगभग 72 प्रतिशत की वृद्धि की है।

प्रमुख बिंदु

- मिड डे मील योजना के पिछले साल के 384 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान 661 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भोजन में अतिरिक्त पोषण मानदंड बढ़ाने के संबंध में विभिन्न खंडों में अध्ययन किया जाए तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने और भोजन के पोषण मानकों को पूरा करने के अलावा इसे स्वच्छ परिस्थितियों में पकाया जाना चाहिये।
- स्कूलों में छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने की समय-सारिणी निश्चित की जानी चाहिये ताकि भोजन की गुणवत्ता की जाँच और निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- ज्ञातव्य है कि योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले भोजन में फोर्टिफाइड आटा, चावल और बाजरा पर आधारित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
- बैठक में बताया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन मिड-डे-मील के साथ 200 एमएल 5 फ्लेवर्ड फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है।

'चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान'

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली के 'ली-मेरीडियन होटल'में 'मेरी माँ फाउंडेशन'द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा, मीडिया समेत कई क्षेत्र की विभूतियों को 'चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान'से नवाज़ा।

प्रमुख बिंदु

- 'मेरी माँ फाउंडेशन'के उपाध्यक्ष दिनेश डागर ने बताया कि संस्था द्वारा भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल की याद में अब तक सात कार्यक्रम किये जा चुके हैं, आज का कार्यक्रम सातवाँ था, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन, समाजसेवा, खेलकूद, मीडिया समेत कई विभूतियों को इस सम्मान से नवाज़ा गया है।
- सम्मानित किये गए लोगों में जसन महला, सतपाल दलाल, अजयदीप लाठर, अनुज मिश्रा, बिजेंद्र बंसल, शिव कुमार, सुनील बाल्याण, नवीन गौतम, रोबिंदर नारायण समेत 150 गणमान्य लोग शामिल थे।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल ने वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिये कार्य किये थे, परंतु उन्होंने गरीब मज़दूर व किसान वर्ग के उत्थान के लिये जो काम किये उनको आज भी लोग याद करते हैं।

हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा काम

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने के लिये जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि जीरो ड्रॉप आउट की नीति के लिये 6 से 18 वर्ष आयु के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिये ट्रैक किया जा रहा है।
- शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के 135 खंडों में दो-दो अर्थात कुल 270 पीएम-श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में यह मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा में फाइव एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान के साथ-साथ सुशासन को भी जोड़ा गया, जिसका बीते आठ वर्ष से अधिक समय में सकारात्मक परिणाम सामने आया। देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैक्नोलॉजी से जोड़ने के लिये दसवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को साढ़े पाँच लाख टेबलेट वितरित किये गए।
- उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिये एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर चार-पाँच गाँवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहाँ तीनों संकाय-कला, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई के साथ स्वरोज़गार के लिये बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा।
- इसी तरह छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिये छापसु (छात्रा परिवहन सुरक्षा) योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई है और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिये एक-एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया।

जीएसटी संग्रहण में हरियाणा पहुँचा देश में चौथे नंबर पर

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा जीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष जहाँ देश में छठे नंबर पर था, इस बार चौथे नंबर पर आ पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रहण में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार राज्य में कुल 33,527 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है।
- उपमुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य को अंतिम तीन महीनों के 2,575 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हैं। इस वर्ष कुल 30,951 करोड़ रुपए प्रदेश में टैक्स के तौर पर राज्य सरकार को मिले हैं।
- पूरे देश में जीएसटी संग्रहण में हरियाणा से ऊपर केवल छोटे राज्य सिक्किम, केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और गोवा हैं।
- दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग में किये गए महत्त्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिये जहाँ 9,200 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, उसकी तुलना में अब तक 9,687 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है जबकि अभी एक माह बाकी है। अनुमान है कि यह आँकड़ा 10,200 करोड़ रुपए को पार कर लेगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी गोदामों, डिस्टलरीज, बॉटलिंग-प्लांट में हाई-सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, उम्मीद है कि इससे लीकेज पर कंट्रोल हुआ है। उन्होंने बताया कि डिस्टलरीज और बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी से डीईटीसी के कार्यालय से मॉनिटरिंग की जाती थी, इस बार हैड-क्वार्टर में भी समानांतर रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि टैक्स की चोरी न हो।
- उन्होंने बताया कि पहले वाहनों की रोड-साईड चैकिंग मैनुअली होती थी, अब अगले एक माह में एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करके अधिकारियों को टेबलेट दिया जाएगा ताकि पकड़े गए वाहन की जीपीएस से लोकेशन, समय और संबंधित सामान की टैक्स चोरी का डाटा ऑन-द-स्पॉट भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी-20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में सिविल 20 (सी-20) के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (जी-20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक) का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से फरीदाबाद में तीन मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।
- उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल शिक्षा फॉर एडवांस्ड क्लिनिकल कैपेसिटी लर्निंग (दिशा) और वी आर विद यू (हम आपके साथ हैं) नामक दो नए प्लेटफार्म भी जारी किये।
- शिखर सम्मेलन के दो दिनों के दौरान, 700 से अधिक सीएसओ, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य के नेताओं ने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने वाली नीतियों को तैयार करने के लिये नीतिगत बैठकों, चर्चाओं और कार्यशालाओं में भाग लेंगे।
- सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सबको आगे बढ़ना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक पद्धति को भी महत्त्व देना जरूरी है।
- उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया में योग पद्धति को अलग पहचान मिली है। हरियाणा सरकार ने भी आयुर्वेदिक पद्धति के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है।
- केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक हजार पार्क व व्यायामशाला तैयार की जा रहीं है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से राज्य में 28 हजार डॉक्टरों की आवश्यकता है। प्रदेश में प्राइवेट चिकित्सक मिलाकर कुल 13 हज़ार डॉक्टरों की संख्या है। हरियाणा सरकार राज्य में चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद व एलोपैथी का संयुक्त कॉलेज बनवाने की अनुमति भी मांगी है ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित किया। अर्जेंटीना, रवांडा और मलावी जैसे देशों के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी माता अमृतानंदमयी (अम्मा) सी-20 की अध्यक्ष हैं।
- सी-20 के वर्किंग ग्रुप इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ की कोर्डिनेटर अमृता अस्पताल की डॉ. प्रिया नायर ने कहा कि वर्किंग ग्रुप का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, बुजुर्गों की देखभाल और समग्र स्वास्थ्य (योग और ध्यान सहित चिकित्सा के पारंपरिक और वैकल्पिक रूप) के क्षेत्र में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान करना, चर्चा करना और उनका समाधान करना है। यह इस प्रकार के मुद्दों से निपटने के लिये नीतिगत ढांचे को तैयार करने में सहायता करेगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि जी-20 एक मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिये काम करता है। सी-20 दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों को जी-20 में विश्व नेताओं तक लोगों की आवाज पहुँचाने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

'मिलेट्स एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा' विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल नेयहाँ एक मीडिया समूह द्वारा 'मिलेट्स एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा'विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम का द्वीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- एक्सपो में किसानों के लिये कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों पर 3 दिन तक मंथन किया जाएगा।
- इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने प्रगतिशील किसानों को किसान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष के रूप में घोषित किया है। जलवायु परिवर्तन, भोजन, पोषण और आजीविका तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई में बाजरा और ज्वार जैसे पोषक अनाज से अपार संभावनाएँ हैं। यह गेहूँ और चावल की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में बाजरा को पोषक आहार के रूप में बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में बाजरा लगभग 10 लाख एकड़ से 12 लाख एकड़ के क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसकी अनुमानित उपज 800 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन होता है। इसके अलावा, ज्वार को लगभग 0.60 लाख एकड़ से 1.10 लाख एकड़ के क्षेत्र में उगाया जाता है।
- इनके अनेक स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए अब लोगों ने इसे अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ज्वार को बढ़ावा देने के लिये किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में होने जा रही 'मिलेट्स कॉन्फ्रेंस' एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, जैसे अनेक विषयों पर चर्चा होगी।
- विदित है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित जी-20 कार्यक्रम के दौरान आए हुए विदेशी मेहमानों को भी मिलेट्स से तैयार किया भोजन खिलाया गया जिसकी प्रतिनिधिमंडल ने भी सराहना की थी।
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ज़िलों में भी अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष -2023 के अंर्तगत ज़िला व ग्राम स्तरीय मासिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें किसानों को पोषक आहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें पोषक आहार को भोजन में सम्मिलित करने से होने वाले कई तरह के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी भी दी जा रही है।
- पोषक आहार केवल पौष्टिक ही नहीं होते बल्कि, उन्हें शुष्क भूमि व कम वर्षा में भी आसानी से उगाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा बाजरा और ज्वार को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहलें की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष-2023 को जन आंदोलन बनाने के लिये कृषि विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 32 करोड़ की दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम ज़िले में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ नामत: बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं का धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम ज़िला में ढाँचागत तंत्र को विस्तार मिला है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो-होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरूग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा।
- गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है।
- इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इसी प्रोजेक्ट के तहत बीते वर्ष नवंबर माह में बसई चौक पर 820 मीटर लंबाई और छः लेन वाले फ्लाईओवर और फुट-ओवर-ब्रिज का भी उद्घाटन किया था।
- मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिये, अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएमगुडगाँव के बीच एक एमओयू हुआ था।
- इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई, जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया।
- इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की।
- करीब 90 एकड़ में फैले सिकंदरपुर जलाशय और वाटरशेड क्षेत्र के पर्यावरण-पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुडगाँव के निवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराना तथा क्षेत्र में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से शहर के शहरी हरित आवरण को बढ़ाना है।
- उल्लेखनीय है कि सिकंदरपुर जल निकाय को पुनर्जीवित कर इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बहाल किया गया है। इस कार्य में आसपास के अतिक्रमणों को साफ करके, अन्य पहलों के बीच, जल निकाय में जमा हुए कचरे और मलबे को हटाया गया और जल निकाय में सीवेज के प्रवाह को बंद कर दिया गया।
- गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) की मदद से इस जल निकाय में पहले से मौजूद प्लास्टिक कचरे को अलग किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कचरे को पास के लैंडफिल में जिम्मेदारी से निपटाया जाए। इसके अलावा, आस-पास के आवासीय क्षेत्रों में वर्षा जल को यहाँ तक लाने के लिये पाइप लाइन डाली गई।
- इस जल निकाय के पुनर्जीवित होने से मानसून के मौसम में क्षेत्र में जलभराव का जोखिम भी कम किया हुआ है। इसके साथ ही क्षेत्र में बाड़ लगाना, मलबे को हटाना, प्राकृतिक पगडंडियों और पैदल रास्तों का निर्माण, वनस्पतियों की स्थानीय प्रजातियों के साथ व्यापक वृक्षारोपण भी सिकंदरपुर इको-रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।

5 दिवसीय सांग महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद के सभागार में विभाग की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित धनपत सिंह सांगी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय सांग महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सांग सबसे प्राचीन और परंपरागत विद्या है। सांग विद्या प्रदेश की संस्कृति और विरासत का अटूट अंग है। इस प्राचीन संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को एक बड़ा स्वरूप देने का कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन मॉरीशिस, लंदन, कनाडा में किया जा चुका है और अब 28 से 30 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

- उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये संस्कृति विकास बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार ही कला, संस्कृति और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिये प्रसिद्ध सांगी धनपत सिंह सांगी की स्मृति में 5 दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन करने के साथ-साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।
- अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक कलाकारों के लिये कई घोषणाएँ की हैं। इन घोषणाओं में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुर्जुग कलाकारों को आजीवन पेंशन देने की भी योजना है।
- जो कलाकार बुर्जुग हो चुके हैं और जिन बुर्जुग कलाकारों के आगे रोजी रोटी का भी संकट है उन कलाकारों को आजीवन पेंशन मिलने से आर्थिक रूप से बड़ा योगदान मिलेगा।

हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा काम

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने के लिये जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि जीरो ड्रॉप आउट की नीति के लिये 6 से 18 वर्ष आयु के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिये ट्रैक किया जा रहा है।
- शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के 135 खंडों में दो-दो अर्थात कुल 270 पीएम-श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में यह मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा में फाइव एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान के साथ-साथ सुशासन को भी जोड़ा गया, जिसका बीते आठ वर्ष से अधिक समय में सकारात्मक परिणाम सामने आया। देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैक्नोलॉजी से जोड़ने के लिये दसवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को साढ़े पाँच लाख टेबलेट वितरित किये गए।
- उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिये एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर चार-पाँच गाँवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहाँ तीनों संकाय-कला, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई के साथ स्वरोज़गार के लिये बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा।
- इसी तरह छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिये छापसु (छात्रा परिवहन सुरक्षा) योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई है और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिये एक-एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया।

पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के हित में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'पत्रकार पेंशन योजना'के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि में अब केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार डीए में की जाने वाली वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की जाएगी।

नोट :

- विदित है कि 26 अक्टूबर, 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'पत्रकार पेंशन योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
- इस योजना के लिये पात्रता मानदंड के अनुसार पत्रकारों को 20 साल का अनुभव तथा 5 साल की अवधि के लिये हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।
- इसके अलावा, पत्रकारों के लिये बीमा योजना, हरियाणा परिवहन बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के साथ-साथ हर ज़िले में मीडिया केंद्र भी स्थापित किये गए हैं, ताकि मीडियाकर्मी बिना किसी असुविधा के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

'प्रापर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने प्रदेश के हर शहर को 'साफ सिटी-सेफ सिटी' बनाने की कड़ी में राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित करने के लिये ऑनलाइन सुविधा 'प्रापर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल' को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- 'प्रापर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल' के जरिये अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रापर्टी के डाटा का सत्यापन http://ulbhryndc.org पोर्टल पर कर सकता है। पोर्टल में प्रापर्टी डाटा में सुधार के विकल्प भी मौजूद हैं।
- कोई भी प्रापर्टीधारक अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों को एक माह अर्थात 15 मई, 2023 तक सत्यापित कर सकता है।
- अब उन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर पर बैठे ही अपने मोबाइल या लेपटॉप के माध्यम से प्रापर्टी का सत्यापन कर सकते हैं।

आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और हिसार एयरपोर्ट के बीच रेल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजवासन-गुरुग्राम-गढ़ी हरसरू-सुलतानपुर-फरुखनगर-झज्जर से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली और महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिसार के बीच माल ढुलाई के साथ-साथ यात्रियों के लिये रेल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को हुई हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) की बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- मुख्य सचिव संजीव कौशल, जो एचआरआईडीसी के अध्यक्षता भी हैं, ने बताया कि इस परियोजना को मंजूरी के लिये रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी।
- पहले चरण में गढ़ी हरसरू-फरुखनगर-झज्जर के बीच रेल संपर्क विकसित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हवाई अड्डे, हिसार को जोड़ा जाएगा। इस रेल लिंक से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, परिवहन दक्षता में सुधार और माल व यात्रियों दोनों के लिये सतत् गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
- एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना गढ़ी हरसरू-फरुखनगर (11 किमी.) मौजूदा सिंगल लाइन और फरुखनगर-झज्जर (24 किमी.) मिसिंग लिंक को डबल लाइन में विकसित किया जाएगा। इस पर 1225 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- झज्जर-रोहतक (37 किमी.) मौजूदा सिंगल लाइन, रोहतक- डोभ भाली-हांसी (68 किमी.) का कार्य उत्तर रेलवे द्वारा प्रगति पर है। हांसी-महाराजा अग्रसेन हिसार (25 किमी.) लाइन को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा।

नोट :

- राज्य में रेल परियोजनाओं के लिये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 1040 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं। इसके लिये जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिये पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 874 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। भारत सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है, जिसके लिये शीघ्र ही सहायता के लिये प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला सेक्टर 12 ए के अंबेडकर भवन में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भीम डिजिटल लाइब्रेरी जनता को समर्पित की और अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर भवन में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने और उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु किताबों की पूर्ति करने और शिक्षा के लिये सॉफ्टवेयर लगवाने में भी हर संभव मदद की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि शिक्षा की अलख जगाने के लिये डिजिटल लाइब्रेरी के विजन से समाज आगे बढ़ेगा और युवाओं का भविष्य उज्जवल और सुखमय होगा। इसके साथ ही वास्तव में बाबा साहब की सोच को भी मूर्त रूप दिया जा सकेगा।
- इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर की व्यवस्था के अलावा लिफ्ट लगवाने का कार्य भी करवाया जाएगा। इसके अलावा यदि कुछ कार्य रह भी जाएंगे तो हैफेड के सी एस आर फंड से करवाए जाएंगे।
- इस अवसर पर निदेशक आईसीएस परिमल कुमार ने कोचिंग सेंटर में टीचिंग फैकल्टी उपलब्ध करवाने एवं जेजेपी सचिव रणधीर सिंह ने लैपटॉप देने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित महू (डॉ. अंबेडकर नगर) में हुआ था। 6 दिसंबर, 1956 को इनका देहांत हो गया था।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर पेशे से मुख्यत: विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) के साथ हाने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक थे।

स्कूल शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन करार किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन के तहत यदि कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है।
- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिये भी समझौता किया गया है।

नोट :

- स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मिलेगा।
- यदि किसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशिक/पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का नि:शुल्क बीमा मिलेगा।
- स्थायी कुल दिव्यांगता, स्थायी और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थायी नुकसान, दोनों आँखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, एक आँख और एक अंग की स्थायी कुल हानि, बोलने की स्थायी कुल हानि, निचले जबड़े का पूर्ण निष्कासन और मैस्टिकेशन का स्थायी कुल नुकसान की स्थिति में 100 प्रतिशत दावा किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त-
  - पूर्णकालिक सहायता के बिना जीवन के लिये आवश्यक दैनिक गतिविधियाँ, दोनों कानों से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 75 प्रतिशत,
  - एक अंग का स्थायी कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत,
  - एक आँख की दृष्टि की स्थायी कुल हानि पर 50 प्रतिशत,
  - एक कान से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 15 प्रतिशत,
  - एक आँख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत,
  - किसी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत,
  - किसी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत,
  - किसी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थायी कुल हानि क्रमश: दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत,
  - किसी भी हाथ की एक उंगली का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत,
  - पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बिग-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत
  - कोहनी, कूल्हे या घुटने का एंकिलोसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपये का शिक्षा लाभ भी मिलेगा।
- अनुबंधित कर्मचारी यदि बैंक में वेतन खाताधारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा नि:शुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस खाता तथा असीमित एटीएम का उपयोग शामिल है।

ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी विश्वकप स्टेप वन-1 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के उत्तरी क्षेत्र केंद्र, बहालगढ़ (सोनीपत) स्थित एक्सीलेंसी सेंटर की तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित हो रही तीरंदाजी विश्वकप स्टेज वन-1 प्रतियोगिता में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- ज्योति सुरेखा वेनम ने स्टेज वन-1 प्रतियोगिता में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ष 2015 में सारा लोपेज के कोलंबियाई राष्ट्रीय चयन स्पर्धा के दौरान बनाए गए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की है।
- भारतीय तीरंदाज ने पहले राउंड में 360 में से 353 और दूसरे राउंड में 360 में से 360 अंक (कुल 713 अंक) के साथ एशियाई रिकॉर्ड बनाया।
- बहालगढ़ स्थित साई की कार्यकारी निदेशक ललिता शर्मा ने बताया कि तुर्की के अंताल्या शहर में 16 से 23 अप्रैल तक तीरंदाजी विश्वकप स्टेज वन-1 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

- विश्व चैंपियनशिप 2021 की रजत पदक विजेता ज्योति सुरेखा ने 72 में से 66 बार सटीक निशाना लगाकर दस अंक प्राप्त किये। इसके साथ ही उन्होंने सारा लोपेज के 2015 में कोलंबियाई राष्ट्रीय चयन स्पर्धा के दौरान बनाए गए विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी कर ली है।
- ललिता शर्मा ने बताया कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की रहने वाली ज्योति सुरेखा वर्ष 2019 से सोनीपत के बहालगढ़ स्थित साई में तीरंदाजी के एक्सीलेंसी सेंटर में अभ्यास कर रही हैं।
- गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली ज्योति सुरेखा हैदराबाद में डीसी हैं। वह पहली तीरंदाज हैं जिन्हें सरकार ने सीधे डीसी के रूप में तैनाती दी थी।

'हरियाणा किराये पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023' अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सरकार ने पिछले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराये या पट्टे के माध्यम से व्यक्तिगत या निजी संस्था के कब्जे वाली सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों की संपत्तियों (दुकानों/मकानों) को बेचने के लिये 'हरियाणा किराये पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023' को अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी/प्रति भूखंड तक की ऐसी सभी संपत्तियों पर लागू होगी, जो 01 जून, 2001 से पहले पट्टे या किराए पर दी गई थी।
- मुख्य सचिव ने बताया कि यह एक 'वन टाइम पालिसी' है जिसके अंतर्गत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- यह नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह नीति शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी।
- विशिष्ट विभागीय अधिनियमों और वैधानिक नियमों के अर्थात् हरियाणा विस्थापित संपत्ति (प्रबंधन और निपटान) नियम 2011, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, हरियाणा पंचायती राज नियम 1995, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961, हरियाणा ग्राम ग्राम शामलात (विनियमन) नियम 1964 और विस्थापित संपत्ति (प्रबंधन और निपटान) अधिनियम 2008 के तहत शासित होने वाली भूमि को भी इस नीति से बाहर रखा जाएगा।

नोट :

- इस नीति में वे संपत्तियाँ शामिल होंगी, जिनका स्वामित्व या प्रबंधन सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है और जो किराए या पट्टे का पैसा अथवा लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी शुल्क के आधार पर खाली ज़मीन, दुकान (दुकानों) जिसका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) मकान और उसका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) उद्योग और खाली भूमि के लिये सरकारी संस्था को देय या प्राप्य है।
- ऐसी संपत्तियों के मामले में, जिनसे सरकारी संस्थाएँ वार्षिक कलेक्टर रेट मूल्य का 8 प्रतिशत और उससे अधिक का किराया पट्टा प्राप्त कर रही हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को वह संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- कब्जे की अवधि के आधार पर बेस रेट पर रियायत-
  - जिस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का 20 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा है, उससे सर्कल रेट का 80 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
  - 30 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 35 वर्ष से कम की अवधि तक कब्जे वाले लोगों से सर्किल रेट का 75 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
  - इसके अलावा, 35 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम की अवधि तक कब्जे वाले लोगों को सर्किल रेट का 65 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
  - 40 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा रखने वालों से सर्कल रेट का 60 प्रतिशत और 45 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 50 वर्ष से कम की अवधि के लिये सर्कल रेट का 55 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
  - जिनके पास 50 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये कब्जा है, उनसे सर्कल रेट का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
- नीति की निगरानी एवं क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इसके लिये तैयार किये गए पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

प्रदेश में सीसीटीएनएस होगा मेघराज क्लाउड में स्थानांतरित

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक ओ पी सिंह ने बताया कि हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) को सफलतापूर्वक मेघराज क्लाउड में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निदेशक ओ पी सिंह आईपीएस ने बताया कि सीसीटीएनएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न भागों को एक पोर्टल पर लाता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान करने, डेटा विश्लेषण और अपराध की रोकथाम की जाती है।
- मेघराज क्लाउड एक स्केलेबल और फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है जो सीसीटीएनएस पर डेटा और उपयोगकर्त्ताओं की बढ़ती मात्रा को सँभाल सकता है, पीक पीरियड्स के दौरान भी सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।
- क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर की सहायता से उपलब्ध सूचनाएँ एक ही प्लेटफार्म पर आसानी व तेजी से उपलब्ध रहेंगी।
- मेघराज क्लाउड डेटा एंक्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नियमित सुरक्षा ऑडिट सहित अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिससे गोपनीयता, अखंडता और आपराधिक रिकॉर्ड, जाँच और मुकदमों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
- मेघराज क्लाउड की मापनीयता और लचीलापन भी उपयोगकर्त्ताओं के कुशल संचालन को सक्षम बनाता है। यह क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर अन्य ऍप्लिकेशंस के उपयोग के साथ आसान एकीकरण की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपस में पारस्परिक डेटा विनिमय और कार्य करने की सुविधा मिलती है।
- प्रदेश पुलिस द्वारा मेघराज में स्थानांतरण करने का निर्णय लेने का कारण इसकी कम लागत भी है। मेघराज क्लाउड के उपयोग से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रखरखाव में निवेश की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की लागत में बचत होती है।
- क्लाउड का पे-एज-यू-गो प्राइसिंग मॉडल कम लागत प्रबंधन और संसाधन के उपयोग की अनुमति देता है, जिससे लंबे समय में लागत बचत होती है। इस प्रोजेक्ट के लिये पुणे की कंपनी से अनुबंध किया गया है।

नोट :

- मेघराज क्लाउड के कंप्यूटिंग संसाधन और डेटा केंद्र के सर्वोत्तम सिस्टम प्रदर्शन, सीसीटीएनएस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। यह प्रदेश पुलिस को वास्तविक समय में महत्त्वपूर्ण जानकारी तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे अपराधों पर त्वरित प्रतिक्रिया होती है।
- मेघराज क्लाउड डिजास्टर रिकवरी तंत्र प्रदान करता है, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में भी डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह सीसीटीएनएस प्रणाली की सुविधा किसी भी व्यवधान से जल्दी उबरने और नागरिकों को निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- विदित है कि आम नागरिकों के लिये सीसीटीएनएस पर शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने, अपराध व् अपराधियों की जानकारी लेने, रोज़गार, किरायेदार, नौकर आदि के सत्यापन करने, पुलिस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं।
- मेघराज क्लाउड को सीसीटीएनएस के हस्तांतरण के साथ, प्रदेश पुलिस उन्नत तकनीकों और क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे का लाभ उठा सकती है। विदित है कि सीसीटीएनएस प्रणाली से थाने के रजिस्टर पर हाथ से लिखने का काम कम होता है और सभी कार्य हिन्दी व अन्य भाषाओं में होता है।इसके अलावा विभिन्न ज़िलों से फॉरेंसिक साइंस और फिंगर प्रिंट ब्यूरो इत्यादि से जानकारी प्राप्त करने में आसानी रहती है।
- प्रदेश पुलिस ने सभी थानों में 10 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देने का निर्णय लिया गया है।सीसीटीएनएस प्रणाली जेल, अभियोजन विभाग, कोर्ट व फॉरेंसिक विभाग के साथ इंटीग्रेटेड है।
- प्रदेश में सीसीटीएनएस में क्राइम डेटा को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैंडर्ड पर अपडेट करने की जिम्मेदारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर है।'एक राज्य एक डेटा'के आधार पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में वर्ष 2022 तक तकरीबन 50 हजार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसका डेटा भी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त आईसीजेएससे समन्वित होने के कारण प्रदेश पुलिस को लावारिस वाहनों व वांछित अपराधियों का डाटा मैच करने में कई केसों में सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री ने प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा सहित 3 नई ई-गवर्नेंस पहलों की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को ई-गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 नई पहलें आरंभ की हैं। इनमें 'प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा', 'ताऊ से पूछो' व्हाट्सएप बॉट और पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विश्राम गृहों की ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिये 'पोर्टल'शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये तीन आईटी पहल निश्चित रूप से राज्य सरकार के पेपरलैस और पारदर्शी शासन के दृष्टिकोण में मील का पत्थर साबित होंगी। इन पहलों से लाभार्थी डिजिटल रूप रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे।
- प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा-
  - प्रो-एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ देने के लिये शुरू किया गया है।
  - परिवार सूचना डेटा कोश में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग के रूप में सत्यापित दिव्यांगों के प्रासंगिक डेटा को हर महीने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
  - सत्यापन के बाद पात्र पाए गए ऐसे सभी दिव्यांगों का डेटा योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार सेवा विभाग के साथ साझा किया जाएगा। सेवा विभाग के ज़िला अधिकारी पेंशन शुरू करने के लिये इन नागरिकों की सहमति लेने के लिये उनके पास जाएंगे। सहमति प्रदान करने वाले सभी दिव्यांगों की अगले महीने से पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
- 'ताऊ से पूछो'व्हाट्सएप बॉट-
  - हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्मित वेब बेस्ड चौट बॉट सॉल्यूशन के साथ-साथ 'ताऊ से पूछो'व्हाट्सएप बॉट नागरिकों के प्रश्नों का तुरंत जवाब देगा।
  - यह सबके लिये आसानी से सुलभ होगा और नागरिक अपने घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर संवाद कर सकेंगे।

नोट :

- इस इंटीग्रेटेड डिजीटल प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है।
- इस प्लेटफॉर्म से नागरिकों के साथ-साथ सरकार का समय भी बचेगा। प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन निश्चित रूप से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगा।
- नागरिक विभिन्न डेटा फील्ड की स्थिति के साथ-साथ आय, विवाह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति, पेंशन और शिकायतों जैसी सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
- एकीकृत ताऊ और व्हाट्सएप बॉट परिवार पहचान संख्या से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देगा। परिवार द्वारा आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, सरकारी नियमों और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों पर सलाह लेने के लिये एकीकृत ताऊ से पूछो व व्हाट्सएप बॉट के साथ संवाद किया जा सकता है।

- पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विश्राम गृहों की ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिये 'पोर्टल'-
  - लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के विश्राम गृहों में कमरों की बुकिंग के लिये विकसित पोर्टल से विश्राम गृहों में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ निजी लोग भी कमरों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
  - इस पोर्टल के माध्यम से अब आवेदक कमरे की उपलब्धता देख सकते हैं, कमरा बुक कर सकते हैं, बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, बुकिंग रद्द कर सकते हैं। इसके लिये आवेदक को बुकिंग के समय ही पूरी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
  - पोर्टल के साथ आई.डी.बी.आई. बैंक की भुगतान गेटवे सेवाओं को जोड़ा गया है। चेक-इन करने के 24 घंटे के अंदर बुकिंग रद्द करने पर बुकिंग राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती होगी। जबकि चेक-इन करने के 24 घंटे से कम समय पर बुकिंग रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
  - इस पोर्टल के माध्यम से अब प्राइवेट व्यक्ति भी इन रेस्ट हाउस में ऑनलाइन कमरा बुक करवा सकते हैं। इनके लिये कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनमें बुकिंग के 15 दिन पहले खाली कमरों के 25 प्रतिशत कमरे बुक करवा सकते हैं।
  - बुकिंग के 7 दिन पहले तक खाली कमरों के 50 प्रतिशत कमरे बुक करवा सकते हैं और बुकिंग के 3 दिन पहले तक खाली कमरों के 75 प्रतिशत कमरे बुक करवा सकते हैं। लेकिन बुकिंग की तारीख से 3 दिन पहले प्राइवेट लोगों के लिये कमरों की बुकिंग नहीं की जाएगी।

131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 10 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति बैठक में राज्य की लगभग 131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, उनमें लोक निर्माण विभाग व जनस्वास्थ्य विभाग की 2-2 तथा 3 फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी की परियोजनाएँ शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने जींद ज़िले के दालमवाला गाँव में नहर आधारित जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की इस पेयजल परियोजना से बेहतवाला, खोकरी, हैबतपुर, मांडो गाँव सहित 5 गाँवों की आबादी को निर्बाध रूप से पेयजल सुलभ होगा ओर इसे हांसी ब्राँच से पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।
- मुख्यमंत्री ने रोहतक शहर के गुरू नानकपुरा में बरसाती पानी निकासी के लिये नया डिस्पोजल बनाने की मंज़ूरी दी गई। इससे महाबीर कालोनी, संजय नगर आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी और इस पर 23.75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
- फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी द्वारा स्थापित की जाने वाली रैनी वैल आधारित 3 पेयजल योजनाओं की मंज़ूरी दी गई। इन तीनों पेयजल परियोजनाएँ 10-10 एमएलडी क्षमता की होंगी, जो यमुना नहर के साथ लगते गाँव भिकुला, मोथूका में लगाई जाएँगी। इन पर 51 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।

नोट :

हरियाणा में पत्रकारों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए हुई

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संत श्री धन्ना भगत जयंती के अवसर पर पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा दो दिवसीय अखिल भारतीय मीडिया मीट कंफेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसी एंप्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए की।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पत्रकारों की पेंशन राशि ऑटोमेशन मोड पर डीए में वार्षिक वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडियाकर्मियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने व उनको और सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा 4000 किमी. तक की मुफ्त मासिक बस यात्रा, पत्रकारों के आश्रितों के लिये आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करना, आधुनिक सुविधाओं से लैस मीडिया केंद्र स्थापित करना, पत्रकार पेंशन और कई अन्य पहलें शामिल हैं।
- उन्होंने कहा कि फील्ड पर काम करने वाले मीडियाकर्मियों के अलावा डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों को भी ऐसी सभी योजनाओं से जोड़ने की योजना है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती पर कैथल ज़िले के गाँव धनौरी में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जींद के हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के नाम पर रखा जाएगा।

हरियाणा के बिजली निगमों ने ए+ ग्रेड हासिल कर किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों की बदौलत प्रदेश की दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ए+ ग्रेड हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस उपलब्धि में 'बिजली चोरी पकड़ो अभियान'एवं 'म्हारा गाँव जगमग गाँव'योजना का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इनसे बिजली कंपनियों के राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों की 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हरियाणा की दोनों बिजली वितरण कंपनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) ने पिछली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में सुधार करते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है।
- वर्तमान रिपोर्ट में भारत भर से 43 राज्य डिस्कॉम, 8 निजी डिस्कॉम और 12 बिजली विभागों को शामिल किया गया था।
- बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन पी.के. दास ने बताया कि यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन दोनों को ए+ ग्रुप में रखा गया है। डीएचबीवीएन ने अपने मूल्यांकन में 85.71 से 89.30 तक सुधार किया है और इसे 9वें स्थान पर रखा गया है।
- इसके अलावा यूएचबीवीएन ने अपने मूल्यांकन में 74.70 से 87.60 तक सुधार किया है और इसे 10वें स्थान पर रखा गया है।
- यूएचबीवीएन ने पिछली रेटिंग में सुधार करते हुए 14वें स्थान से 10वाँ स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार डीएचबीवीएन ने पिछली रेटिंग में सुधार करते 12वें स्थान से 9वाँ स्थान हासिल किया है।

नोट :

हरियाणा विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिये याचिका समिति का चेयरपर्सन विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को नामित किया गया है, जबकि सदस्यों में विधायक जगबीर सिंह मलिक, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक, लीला राम, लक्षमण सिंह यादव, संजय सिंह, राम निवास तथा सोमबीर सांगवान शामिल किये गए हैं।
- इनके अलावा, लोक लेखा समिति में विधायक वरुण चौधरी को चेयरपर्सन तथा सदस्यों में विधायक सीमा त्रिखा, राम कुमार कश्यप, नरेंद्र गुप्ता, भव्य बिश्नोई, अमित सिहाग, सुरेंद्र पंवार, जोगी राम सिहाग व रणधीर सिंह गोलन शामिल हैं।
- विधानसभा की नियम समिति में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पदेन चेयरपर्सन तथा सदस्यों में विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, गीता भुक्कल, घनश्याम दास अरोड़ा, डॉ. अभय सिंह यादव, नैना सिंह चौटाला व सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं।
- इसी प्रकार अधीनस्थ विधान समिति में विधायक ईश्वर सिंह को सभापति तथा सदस्यों में विधायक जगबीर सिंह मलिक, अभय सिंह चौटाला, जयबीर सिंह, डॉ. अभय सिंह यादव, बिशंबर सिंह, अमित सिहाग, इंदुराज व हरियाणा के महाधिवक्ता और विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

दृष्टि The Vision

नोट :